RAJYA SABHA

Tuesday, the 16th May, 1995/26th Vaisakha, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*561. [*The questioner (Shri LRamji Lal) wasabsent. For answer, vide Col.. ....infra]*

मध्य प्रदेश में सांची में विदेशी पर्यटक

*562. **श्री राघवजी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सांची (मध्य प्रदेश) में विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो सांची में पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिये मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो, तो इसके क्या कारण हैं और क्या निकट भविष्य में इस दिशा में कोई योजना तैयार की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया हैं ।

विवरण

(क) जी, हां । पिछले तीन वर्षों के दौरान सांची में विदेशी पर्यटक आगमन में अनुकूल वृद्धि रही है । 1992, 1993 और 1994 के दौरान सांची का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों संख्या निम्नानुसार थी :—

वर्ष	पर्यटक आगमन	%परिवतन
1992	1573	—
1993	1898	(+)20.7
1994	2453	(+)29.2

(ख) और (ग) किसी स्थान पर पर्यटक आधारभूत सुविधाओं का विकास करना मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है । पर्यटन विभाग, भारत सरकार, पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान, सांची में पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । 1985–86 में, पर्यटन विभाग ने, सांची में एक कैफेटेरिया और प्रसाधन/पेय जल सुविधाओं के निर्माण हेतु 11.32 लाख रू. की राशि की आर्थिक सहायता रिलीज की थी । यदि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव भेजा जाए, तो सांची में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से अतिरिक्त पर्यटक सुविधाएं प्रदान कराई जा सकती हैं ।

श्री राघवजी : सभापति जी, सांची में विश्व प्रसिद्ध स्तूप है और उसके द्वार जो बने हैं, वे अद्वितीय है पुरातत्व की दृष्टि से भी और बौद्ध धर्म के तीर्थ की दृष्टि से भी । सांची का इतना बड़ा महत्व होने के बावजूद भी और जहां पर प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ रही हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया हैं कि 1994 में 29.2 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई लेकिन इसके बावजूद भी 1985–86 में केवल 11 लाख रूपए कैफेटेरिया के खर्च हुए । इसके अलावा आज तक दस सालों में एक

रुपया भी केन्द्रीय पर्यटन विकास विभाग ने वहां पर खर्च नहीं किया जबकि वहां पर आवास के लिए भी काफी असुविधा है, केवल एक टूरिस्ट लाज है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए भी और देशी पर्यटकों के लिए भी वहां पर आवास सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए किसी योजना पर विचार करेगी और क्या होलिडे-होम्स या ऐसी किसी प्रकार की योजना के बारे में विचार करेगी ?

श्रीमती सुखबंस कौर : सर, यह सही है कि सांची में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में तीर्थ यात्रा पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा बनी रही है । हमारी यह कोशिश है कि हम तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं लेकिन एक बात मैं अपने आनरेबल मैम्बर को बताना चाहती हूं कि जो डेवलपमेंट आफ इनफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्राइमरिली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पान्सिबिलिटी है । हम डिपार्मेंटट आफ टूरिज्म से कुछ आर्थिक सहायता उनको देते हैं । वे अपने प्रपोजल्स बना कर लाते है और हम उनको सहायता देते हैं । जो भी वे प्रपोजल लाते हैं, हमारी यह कोशिश होती हैं कि हम उनको सहायता दें । जहां तक सांची का सवाल है, यह सही है कि हमने सिर्फ 11 लाख रुपया दिया है लेकिन जैसा मैंने बताया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे और पैसा मांगेगी तो हम जरूर देंगे । वहां पर भी सांची में एक ट्रैवल्स लाज है, एक कैफेटेरिया है, उसके साथ दो कमरे हैं, एक पी.डब्ल्यू.डी. गैस्ट हाउस है और वहां पर एक महाबोधी सोसायटी का डार्मिटरी टाइप रेस्ट हाउस है । इसके अलावा भोपाल जो उसके नजदीक पड़ता है, वहां पर भी काफी ऐकोमोडेशन अवेलेबल है और मेरे पास उसके आंकड़े हैं । तकरीबन 306 कमरे भोपाल में भी हैं । इसलिए हमारी तरफ से अगर कुछ और कमरे या अन्य सुविधाएं उनको चाहिए होंगी तो हम उनको जरूर सहायता देंगे ।

श्री राघवजी : सभापति जी, मैं माननीय मन्त्री महोदया का इस बात के लिए आभार मानता हूं कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो वे इस पर विचार करेंगे लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से खजुराहो में हवाई अड्डा है और वहां पर हवाई यात्रा से सीधे खजुराहो पहुंचा जा सकता है, खजुराहो से किसी भी दृष्टि से सांची कम नहीं है और वहां पर पहुंचने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । खजुराहो और सांची को भी जोड़ा जा सकता था और यह कोई राज्य सरकार का मामला तो नहीं है, सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के उड्डयन *विभाग का मामला है* । तो हवाई अड्डा नहीं हैं वहां पर नंबर एक और नंबर दो, अगर वहां पर यात्री पहुंच जाए तो उसके आस-पास जितने स्थल है देखने के लिए, उदयगिरी केव्ज विदिशा की, हेलिओडोर पिलर विदिशा का और सप्तधारा, ये तीन-चार स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए कोई भी व्यवस्था, किसी वाहन की व्यवस्था नहीं है वहां पर । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर हवाई यात्रा की व्यवस्था करेंगे ताकि टूरिस्ट सीधे सांची में जाकर ठहर सकें और उनको भोपाल जाने की आवश्यकता न पड़े, क्या इस तरह का कोई प्रबन्ध आप करेंगे ? दूसरा, शताब्दी सांची रेलवे स्टेशन से ही गुजरती है तो शताब्दी को वहां रोकने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी ? साथ ही आसपास के स्थलों को देखने के लिए टूरिस्ट बसों की व्यवस्था, क्या आपका मंत्रालय करने की स्थिति में है, इसका आश्वासन क्या आप दे सकते हैं ?

श्रीमती सुखबंस कौर : पहली बात तो यह है कि जहां तक एयर कनेक्शन का सवाल है, भोपाल के लिए डाइरेक्ट फ्लाइट है, इंडियन एयर लाइंस की और अर्चना एयरवेज की फ्लाइट्स जाती हैं । रेल की भी वहां लाइन है जो झांसी और इटारसी सेक्शन की हैं । सांची के बारे में बात करनी पड़ेगी, देखना होगा कि उसका क्या हो सकता है । इस बारे में मैं इस टाइम कुछ नहीं कह सकती कि वहां शताब्दी टाइप ट्रेन चलेगी या नहीं

चलेगी । जहां तक वहां के नजदीक के स्थानों को देखने का सवाल है वह प्राइवेट इंटरप्रोनर्स से भी हम कोशिश करते है कि वे अपनी लक्जरी बसेस टूरिस्ट्स के लिए चलायें और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाये ।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी सांची एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल भी है और इसका प्राचीन इतिहास हमारी संस्कृति और इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, जिसमें जितने भी बौद्ध स्थल हैं, उनके लिए एक समान कार्य योजना बनाकर पर्यटन की अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिससे विदेशी पयटकों के लिए अधिक से अधिक सुविधा, जाने की, ठहरने की और देखने की हो सके । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जापान सरकार ने या जापान के महाबोधि सोसाइटी ने या फूजी गुरूजी, जो जापान के सबसे बड़े बौध संत थे उनकी सोसाइटी ने भारत सरकार को इस तरह का कोई आश्वासन दिया है कि वे आर्थिक सहयोग और सहायता देने के लिए तैयार हैं ताकि भारत और नेपाल में जो भी बौद्ध स्थल हैं, उन्हें एक सरकिट के साथ जोड़ा जा सके ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती सुखबंस कौर : हमारे जितने भी बौद्ध धर्म स्थान हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसके लिए हम लोगों ने कई स्कीमें बनाई हैं । हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहां सुविधाए उपलब्ध करायें । हम लोगों ने बिहार में, यू०पी० में और सांची में थोड़ा किया है । इसके अलावा हम लोगों ने आन्ध्र प्रदेश में भी पैसा दिया है और वहां करने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन स्कीम सारे ही बौद्ध धर्म के स्थानों के लिए एक जैसी हों, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है । अलग अलग जगहों के लिए अलग-अलग किया गया है ।

जहां तक जापान का सवाल है वहां ओ०ई.सी०एस० फंड जो बिहार और यू०पी० के लिए दिया गया था, अभी वह खर्च हो रहा है । ऐसे आफर हमारे पास आते रहे हैं और बातचीत होती रहती है । लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि जापान से हम पैसा लेंगे या नहीं लेंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह : यह तो भारत सरकार की अक्षमता है कि लोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन वह लेने के लिए तैयार नहीं है और स्वयं भी कोई योजना नहीं बना रही है । यहां पर जो बौद्ध पयटक आते हैं उनकी शिकायत है कि भारत सरकार इसमें सहयोग नहीं दे रही है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि...

श्रीमती सुखबंस कौर : ऐसी बात नहीं है । वह देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसमें कई चीजें होती हैं । हमें उसमें बहुत कुछ देखना होता है । सिर्फ यह नहीं होता कि कोई सरकार पैसा देने के लिए तैयार है तो हम एकदम ले लें । उस पर विचार करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है । अगर यह देश के लिए और उन जगहों की प्रगति के लिए आवश्यक होगा तो हम जरूर लेंगे ।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की इसमें कमजोरी नहीं है । क्योंकि जब उनसे ज्यादा पैसा मांगते हैं तो कम्पलीशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए । उसके आधार पर पैसा रिलीज होता है । लेकिन अधिकतर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक बिहार का सवाल है, वहां से सर्टिफिकेट आता ही नहीं है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने सांची और मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की बात उठायी । बिहार के ऊपर आप इल्जाम लगाकर इस तरह से प्रश्न का उत्तर न दें ।

श्री गुलाम नबी आजाद : यू.पी. और बिहार, दोनों स्टेटों की अधिकतर वही हालत है । उनके पहले के प्रोजेक्ट हैं—: वे प्रोजक्ट हैं, बिहार, यू.पी. और

महाराष्ट्र में । जहां तक बिहार और यू०पी० का सवाल है वह बहुत पीछे हैं और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वह बहुत आगे है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह तो आपका स्टेट है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे स्टेट का सवाल नहीं है (**व्यवधान**)

श्री राघवजी : यह मध्य प्रदेश का मामला है (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : जब तक हमारी पिछली परफारमेंस अच्छी नहीं होगी तब तक अगले के लिए पैसा मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है (**व्यवधान**)

श्री जलालुद्दीन अंसारी : बिहार ने जितनी योजनाएं भेजी हैं, सब लौटा देते हैं, मैं सबूत देना चाहता हूं (**व्यवधान**)

†[شری جلال الدین انصاری: بہار نے جتنی یوجنائیں بھیجی ہیں۔سب لوٹا دیتے ہیں۔میں ثبوت دینا چاہتا ہوں۔۔۔"مداخلت"۔۔۔]

श्री कैलाश नारायण सारंग : मंत्री महोदय से प्रश्न किया मध्य प्रदेश का और उन्होंने बिहार की बात शुरू कर दी । सवाल यह है कि सांची विश्व विख्यात स्तूपों के लिए और जापान तथा श्रीलंका दोनों राष्ट्र सांची के विकास के लिए इंटरेस्टेड हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने 1991–92 में एक बहुत बृहद योजन बनाकर वहां के पहाड़ी विकास के लिए, सुरंग बनाने के लिए एक योजना भेजी थी जिसमें जापान और श्रीलंका भी इंटरेस्टेड हैं । लेकिन विगत 10 वर्षों से सांची के प्रति जिस तरह का दुर्व्यवहार केन्द्र सरकार की ओर से हो रहा है, वह यहां उल्लखनीय है । मंत्री महोदय, क्या मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बृहद योजना के बारे में केन्द्र सरकार ने कुछ विचार किया ? क्या श्रीलंका और जापान सरकार जो वहां करीब दो सौ करोड़ रूपया इनवेस्ट करने के लिए तैयार है, क्या उस दृष्टि से भी कुछ आपसे विचार किया या कोई प्रस्ताव है, कोई चर्चा हो रही है ? मंत्री जी यह बताने की कृपा करें ।

श्री गुलाम नबी आजाद : पिछले पांच सालों से चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो किसी भी मंत्री या मुख्य मंत्री से इस बारे में मुझसे कोई चर्चा नहीं की । (**व्यवधान**)

श्री लक्खीराम अग्रवाल : कोई प्रस्ताव भेजा है क्या ? (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : चर्चा के बगैर प्रस्ताव कहां होगा । चर्चा तक नहीं की (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : मंत्री महोदय, जरा तलाश कर लीजिये । प्रस्ताव लिखित है । मुझे खुद पता है and I am personally interested in it, इसलिए मैं कह रहा हूं ।

श्री गुलाम नबी आजाद : पिछले तीन साल से मैं भी इस मिनिस्ट्री में हूं । किसी का इंट्रेस्ट होता तो चर्चा तो करते (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : मैं 1991–92 का बोल रहा हूं (**व्यवधान**)

श्री लक्खीराम अग्रवाल : आप दिलवा लीजिये . . . (**व्यवधान**)

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Thank you, Mr. Chairman. Though the question pertains to Sanchi, I would like to put a general question with regard to tourism development.

MR. CHAIRMAN: But it has to be focussed on Sanchi.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Sir, the Minister has replied that the development of tourist facilities at any place is primarily the responsibility of the State Governments. The Department of Tourism, Government of India, extends financial assistance to the State Governments for development of tourist facilities on the basis of proposals received from them. This is the reply. I would like to know whether the proposals of the State Governments have been fully honoured by the Central Government and also whether full financial assistance has been given to the State Governments for completion of those projects. I am asking this because there is a guest house at Rameswaram in Tamil Nadu and for want of financial assistance from the Central Government, there is no compound, cattles are allowed into the guest house and it is free for all. It is not being utilised at all. I would like to know whether any monitoring facility is provided by the Central Government to find out whether the funds are being utilised properly and also whether full amount has been sanctioned to the State Governments according to the proposals made by them.

SHRIMATI SUKHBANS KAUR: I would like to reiterate that, tourism being a State Subject, it is primarily the responsibility of the State Government to build the infrastrucure. We do give a certain amount of financial assistance and in 99 per cent of the proposals that are given to us in proper from—in the sense that they have to fulfil certain conditions—money is always given to them. There is no question of our not honouring the commitments that we have made.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: I asked a specific question about the guest house at Rameswaram.

SHRI SUKHBANS KAUR: I do not have the specific answer to that because the question is mainly for Madhya Pradesh.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बार बार यह कहा कि पर्यटन विभाग राज्य विषय है । मैं एक ऐसे प्रकल्प की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो राज्य से अधिक केन्द्र का विषय होना चाहिये । कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे दुर्गम यात्रा है और इस यात्रा के लिए भारत और चीन सरकार के संबंधों पर निर्भर रह कर यात्री जाते हैं । कैलाश मानसरोवर मापी चाहता हूं, कैलाश मानसरोवर के अंतर्गत है । तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में मेरे मित्रों ने बताया है कि चीन सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं और भारत सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाएं बहुत कष्टकर है, नम्बर एक और दूसरा यह है कि यह बहुत खर्चीली यात्रा है । एक एक यात्री को उस पर 30,000 रूपए खर्च करने पड़ते हैं । क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार तीर्थ यात्रियों को कुछ सहायता भी देना चाहती है जैसे कि हज के यात्रियों को बराबर दी जाती है ?

MR. CHAIRMAN: Is the Minister willing to answer?

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, Sir.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : राज्य और केन्द्र के बारे में तो बताएं ।

MR. CHAIRMAN: It does not relate to this qqestion.

Refusal by Qattar to Air India flight to land

*563. SHRI VIRENDRA KATARIA
SHRI SURESH KALMADI :

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Qatar refused an Air India flight to land in its territory on 21st of April, 1995.

†The question was actually asked on the floo of the House by Shri Virendra Kataria.